



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 978 राँची, शुक्रवार,

12 अक्टूबर, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

8 अक्टूबर, 2018

विषय :- राज्य में Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation को शैक्षणिक/स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने हेतु रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ।

संख्या-5/स०भू० विविध (Non-Profit/Charitable/Spiritual)-104/18-4175,-- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 25 सितम्बर, 2018 के मद संख्या-11 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य में Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation को शैक्षणिक/स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने हेतु रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत् नीति निर्धारण किया जाता है :-

(क) Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation के आवेदकों को शैक्षणिक/स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा संस्थान खोलने के योग्य पाये जाने की अवस्था में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा दिये जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित संस्थाओं को भूमि के बाजार मूल्य (Circle rate) का 50 प्रतिशत Rebate प्रदान किया जाय। तदनुसार प्रचलित बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत राशि सलामी के रूप में एकमुश्त

देय होगा तथा उक्त भुगतेय सलामी का एक प्रतिशत लगान वार्षिक रूप से भुगतेय होगा। भूमि पर अवस्थित संरचना व वृक्षादि की राशि अलग से भुगतेय होगी।

- (ख) वैसे Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation, जो सुदूरवर्ती (Remote) क्षेत्र/ Backward Blocks में शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थान खोलने हेतु इच्छुक होंगे, को भूमि के बाजार मूल्य (Circle rate) का 75 प्रतिशत Rebate प्रदान किया जाय। तदनुसार प्रचलित बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत सलामी के रूप में एकमुश्त देय होगा तथा उक्त भुगतेय सलामी का एक प्रतिशत लगान वार्षिक रूप से भुगतेय होगा। भूमि पर अवस्थित संरचना व वृक्षादि की राशि अलग से भुगतेय होगी। सुदूरवर्ती (Remote) क्षेत्र/ (Backward Blocks) की सूची सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित की जायेगी।
- (ग) भूमि पर अवस्थित संरचना का मूल्यांकन, भवन के लिए भवन निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता द्वारा एवं वृक्ष का मूल्यांकन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित संस्था को इससे संबंधित दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा।
- (घ) भूमि 30 वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती पर 1/- रु० की टोकन राशि प्राप्त कर नवीकरण किये जाने के विकल्प के साथ प्रदान की जायेगी।
- (ङ.) संबंधित विभाग से भूमि आवंटन हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि के लीज बंदोबस्ती संबंधी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को उपस्थापित किया जायेगा। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरान्त राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।
- (च) Non-Profit/Charitable/Spiritual Organisation में वैसी संस्थाओं को ही रियायती दर पर भूमि प्रदान की जायेगी, जिनका Education तथा Health के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण/उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करने का Track Record रहा हो एवं जिनको उक्त क्षेत्र में कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त हो।
- (छ) उक्त के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा एक मानक तय किया जायेगा, जिसके आधार पर उक्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यांकन हो सके, ताकि उन्हें रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराया जा सके। जो संस्था विशुद्ध रूप से Charitable अथवा spiritual उत्थान के क्षेत्र में सेवा दे रही हो, वैसी संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटित नहीं की जायेगी।
- (ज) राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के अंदर शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थान चालू न करने पर भूमि वापस ले ली जाएगी तथा उक्त संस्था के विरुद्ध भूमि का पूर्ण

मूल्य/दण्ड अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। मात्र शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थान के लिए ही भूमि दी जाएगी।

- (झ) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के आलोक में इन संस्थानों को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराते समय वनभूमि अथवा जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) किस्म के भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में सुसंगत प्रावधानों/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वाद संख्या-202/95 में पारित दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के आदेश के आलोक में भारत सरकार/सक्षम स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। राज्य में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्यों के चारों ओर घोषित Eco sensitive zone में पड़ने वाले भूमि के आवंटन के स्थिति में उसके अन्दर विनिर्दिष्ट कार्य हेतु ESZ Monitoring Committee/SBWL/NBWL के पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी।

ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार द्वारा वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों में लगाये जाने वाले मुख्य मानक शर्तों के अनुसार अपयोजित की जानेवाली वनभूमि की Net Present Value (NPV) जमा कराना एवं समतुल्य उपयुक्त गैर वनभूमि/जंगल-झाड़ी भूमि Compensatory Afforestation हेतु उपलब्ध कराने के साथ उस पर वृक्षारोपण किए जाने हेतु खर्च होनेवाली राशि CAMPA मद में जमा कराना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए जानेवाले शर्तों तथा EIA के शर्तों का भी पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विषयक कार्य हेतु दी जानेवाली भूमि पर खड़े वृक्षों के पातन के पूर्व माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा गठित High Powered Committee से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षित क्षेत्रों (Protected area) में यथायोग्य NBWL की स्वीकृति भी आवश्यक होगी।

- (ज) Non Profit/Charitable/Spiritable/Organisation को शैक्षणिक/स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित स्कूल/अस्पताल को लीज बंदोबस्त भूमि का नवीकरण तभी किया जायेगा जब उक्त संस्थान कार्यरत अवस्था में होंगे।
- (ट) उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के आलोक में Non Profit/Charitable/Spiritable Organisation राज्य सरकार से रियायती दर पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से शैक्षणिक/स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने हेतु भूमि प्राप्त कर सकेगा तथा सभी मापदण्ड को पूरा करत हुए AICTE/MCI/UGC/NCTE से मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त सत्रों का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ठ) Non Profit/Charitable/Spiritable Organisation को शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थान खोले जाने से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आलोक में संबंधित उपायुक्तों को आवश्यकतानुसार Limitation करने हेतु निदेशित किया जायेगा।

- (ड) दो वर्षों के अन्तराल के बाद अथवा आवश्यकता महसूस होने पर इससे पूर्व भी प्रशासी विभाग इस नीति के प्रभावों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर सकेगा।

उपरोक्त शर्तों एवं बंधेजों के अंतर्गत संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा संबंधित संस्थान खोलने हेतु रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव गठित कर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को प्रेषित किया जायेगा एवं विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

2. अन्य सभी शर्तें विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4306/रा., दिनांक 24 अक्टूबर, 2014, संकल्प

ज्ञापांक-48/रा०, दिनांक 3 जनवरी, 2017 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल के प्रावधानों तथा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होंगे।

ह०/-

उदय प्रताप,
सरकार के अपर सचिव ।
